

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

06 / 2017
24.04.2017

सरकार जरिये तहसीलदार देवली जिला टोंक राज०

.....प्रार्थी

बनाम

रामकरण पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी बनेडियाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक राज०

..... अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) भू-आवंटन नियम 1970

उपस्थिति : (1) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 31.12.2020

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1984 को प्रतिपक्षी को आ०ख०नं० 793 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली में आवंटन किया गया है। प्रार्थी ने उक्त आवंटन को विधि विरुद्ध एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस अप्रार्थी की गई। आवंटन सम्बन्धी पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया है कि आवंटन दिनांक 02.06.1984 को ग्राम बनेडियाखुर्द के गत बन्दोबस्त के खसरा नम्बर 793 में रकबा 3 बीघा भूमि प्रतिपक्षी को आवंटन हुई थी। उक्त आवंटन के आधार पर बिना कब्जा काश्त व बिना सक्षम न्यायालय के आदेश मात्र आवंटन पत्र के आधार पर 10 वर्ष बाद बीसलपुर परियोजना के डूब की धारा 4 व 6 गजट प्रकाशन के उपरान्त नये भू-प्रबन्ध के खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.75 है. को आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 21.04.1994 स्वीकृत किया गया एवं जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 के खाता संख्या 1 में उक्त गैर खातेदारी के नामान्तरकरण का नोट अंकित किया गया। नामान्तरकरण नियम विरुद्ध होने से नागा. संख्या 147 दिनांक 21.04.1994 को निरस्त करने हेतु तहसीलदार देवली द्वारा माननीय न्यायालय अति. कलेक्टर टोंक में



.....
राजकरत जिला कलेक्टर
टोंक

भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स प्रकरण तैयार कर प्रकरण संख्या 23/2000 दिनांक 10.10.2001 को दर्ज करवाया गया। माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर टोंक द्वारा उक्त रेफरेन्स में दिनांक 31.03.2002 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रकरण को नामान्तरकरण संख्या 147 को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रेफरेन्स प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एल आर/ 405/02/टोंक उनवान सरकार बनाम रामकरण दर्ज कर प्रकरण में दिनांक 16.12.2003 को निर्णय पारित किया " ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली के खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.75 है. को सिवायचक से अप्रार्थी रामकरण को गैर खातेदारी देने हेतु जो नामान्तरकरण संख्या 147 दिनांक 21.04.1994 को अप्रार्थी के पक्ष में खोला गया है। उसे निरस्त किया जाता है तथा भूमि पुनः सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये।"माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना में तहसीलदार ने ग्राम बनेडियाखुर्द में खसरा नम्बर 1123 रकबा 0.75 है. भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 14.06.2004 से उक्त भूमि को पुनः सिवायचक दर्ज कर दी गई। अप्रार्थी के हक में खोले गये नामान्तरकरण संख्या 147 में भी आवंटि का आवंटित भूमि पर कब्जा होने का कोई उल्लेख नहीं है। मात्र आवंटन सूचि में आवंटन का उल्लेख है।

आवंटन तिथि से आज तक आवंटि ने आवंटित भूमि को कभी काश्त नहीं की है और ना ही मौके पर आवंटि का कब्जा है। उक्त भूमि बीसलपुर बांध में डूब जाने के कारण काश्त हेतु उपलब्ध नहीं रही है। आवंटि को नामान्तरकरण संख्या 147 से गैर खातेदारी अवैधानिक रूप से दिये जाने से नवीन खसरा नम्बर 1123 में से 0.75 है. रकबे पर आवंटि का कब्जे-काश्त नहीं होने से किसी प्रकार की तरमीम नहीं की गई। आवंटि के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। अतः आवंटन निरस्त योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1984 को प्रतिपक्षी को आ0ख0नं0 793 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली में नियमानुसार आवंटन की गई है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थी काश्त करता है। आवंटि द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है। प्रार्थी 33 वर्ष बाद आवंटन को निरस्त करवाना चाहता है जो सही नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिपक्षी को भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 02.06.1984 को आ0ख0नं0 793 रकबा 3 बीघा भूमि वाके ग्राम बनेडियाखुर्द तहसील देवली में आवंटन किया गया है।



देवे
दावारकत जिला कलेक्टर
टोंक

अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है, आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काशत नहीं रहा है, आवंटी सद्भावी कृषक नहीं है। विवादित भूमि आज दिनांक तक काशत नहीं की गई है।

अभिभाषक अप्रार्थी का तर्क है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी काशत करता है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की गई है। अप्रार्थी भूमिहीन कृषक है तथा आवंटन शर्तों की पूर्ण पालना की है, परन्तु इसकी तायद मे कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है।

पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजात नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन होने के पश्चात उक्त भूमि काशत की गई हो।

राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 की उपधारा (3) मे आवंटिती को आवंटन के प्रथम वर्ष मे भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पडेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष मे आवश्यक रूप से जोतने की शर्त है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त नियम की पालना मे आवंटित भूमि को तत्समय नहीं जोता तथा उसके पश्चात भी आज तक नहीं जोता है।

आवंटी द्वारा आवंटित भूमि मे काशत न कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है। राज्य सरकार का उद्देश्य भूमिहीन कृषको को भूमि आवंटन कर उनके द्वारा भूमि काशत कर उसके जीविकोपार्जन हेतु दिये जाना है, परन्तु जब आवंटी द्वारा भूमि काशत नहीं की जाती है तो उस आवंटन का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः ऐसी स्थिति मे आवंटन यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

फलतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी रामकरण पुत्र श्योदान जाति गुर्जर निवासी बनेडियाखुर्द तहसील देवली जिला टोंक को दिनांक 02.06.1984 को ग्राम बनेडियाखुर्द की आ0ख0नं0 793 मे रकबा 3 बीघा भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Ar
(सुब्रह्म चिखोवर)
अति.जिला कलेक्टर, टोंक